Drishti IAS

करेंट अफेयर्स झारखंड

अक्तूबर 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखंड **3**

- ‘अबुआ वीर दिशोम अभियान’ का शुभारंभ 3
- राज्यस्तरीय खेलो झारखंड कबड्डी प्रतियोगिता प्रारंभ 4
- झारखंड के जमशेदपुर में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव ‘आदि महोत्सव’ का उद्घाटन 4
- ‘युवा प्रतिभा’ के शीर्ष 20 प्रतिभागियों में राँची के अंकित का चयन 6
- झारखंड में ‘ए-हेल्प ’कार्यक्रम का शुभारंभ 6
- ‘अमृत’ मिशन (AMRUT) के तहत देश के 500 शहरों में झारखंड के पाँच शहर शामिल 7
- झारखंड में होगा मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 9
- मुख्यमंत्री ने झारखंड के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को किया पुरस्कृत 9
- इंस्पायर अवॉर्ड मानक के अंतर्गत आइडिया देने के मामले में झारखंड देशभर में छठे स्थान पर 11
- राँची के सात वर्षीय छात्र विवान को मिला स्टार आर्टिस्ट अवॉर्ड 11
- स्कूली बच्चों के लिये ऑनलाइन एजुकेशन ऐप ‘जे गुरुजी ऐप’ 12
- झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बने ओडिशा के नए राज्यपाल 13
- 15 नवंबर को राँची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का होगा भूमि पूजन 13
- राँची को एक और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मिली मेज़बानी 14
- ‘अबुआ आवास योजना’ के लिये अलग से गठित होगी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट 14
- प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडेय को मिला ‘लाडली मीडिया अवॉर्ड’ 16
- झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) का डिजि लॉकर नवंबर से ऑनलाइन 18
- मुख्यमंत्री ने झारखंड के सबसे लंबे पुल व 21 अन्य योजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन 19

नोट :

झारखंड

'अबुआ वीर दिशोम अभियान' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

2 अक्तूबर 2023 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राज्य में 'अबुआ वीर दिशोम अभियान 2023' का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर ग्राम स्तर पर वनाधिकार समिति का गठन-पुनर्गठन करने, वन पर निर्भर लोगों और समुदायों को वनाधिकार पट्टा दिये जाने के लिये शपथ ली गई।
- शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वनाधिकार के लिये प्रस्तावित अबुआ वीर दिशोम अभियान, 2023 (वन अधिकार अभियान, 2023) के क्रियान्वयन और वन अधिकार नियम के अनुसार अनुशंसा करने, जल, जंगल और ज़मीन तथा इसके संसाधनों की रक्षा के लिये समर्पित और संगठित प्रयास करने की शपथ ली गई।
- राज्य के 30 हज़ार से अधिक ग्राम सभाओं ने वन अधिकार अधिनियम के अतर्गत ग्राम स्तर पर वनाधिकार समिति का गठन-पुनर्गठन तीन अक्तूबर से 18 अक्तूबर तक होगा।
- उपायुक्त अपने-अपने ज़िलों में अक्तूबर के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में ज़िलास्तरीय वन प्रमंडल पदाधिकारी और राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामस्तरीय वनाधिकार समिति में की जाने वाली कार्रवाई के लिये सभी प्रकार के भू-अभिलेख फॉरेस्ट मैप की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये पूरी कार्य योजना तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।
- एफआरसी सेल का भी होगा गठन: ज़िलास्तर, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर एफआरसी सेल का गठन सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रामस्तरीय वनाधिकार समिति की ओर से पेश किये गए दावों पर ग्रामसभा द्वारा लिये गए निर्णय से एसडीएलसी को अनुशंसित दावों की एक प्रति प्रखंडस्तरीय एफआरए सेल में दी जाएगी।

राज्यस्तरीय खेलो झारखंड कबड्डी प्रतियोगिता प्रारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 3 अक्तूबर, 2023 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के शिक्षा परियोजना परिषद के तत्त्वावधान में राँची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में राज्यस्तरीय खेलो झारखंड कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।

प्रमुख बिंदु

- झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के एसडीईईओ बादल राज और झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।
- कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अंडर-14/17/19 बालक एवं बालिका वर्ग में राज्य के 1728 खिलाड़ी और 288 कोच व मैनेजर भाग ले रहे हैं।
- प्रतियोगिता के आधार पर चयनित खिलाड़ियों के लिये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अंडर-14 बालक टीम रांची में और अन्य वर्ग की टीमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में होने वाली राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता में भाग लेंगी।

झारखंड के जमशेदपुर में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 'आदि महोत्सव' का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

7 अक्तूबर, 2023 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के जमशेदपुर में 'आदि महोत्सव' राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- यह विशाल कार्यक्रम 7 से 16 अक्तूबर, 2023 तक जनजातीय मामलों के मंत्रालय के ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीआरआईएफईडी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- आदिवासी उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का वार्षिक उत्सव 'आदि महोत्सव' देश भर की जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
- इस वर्ष यह महोत्सव विशेषरूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) और वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) लाभार्थियों सहित 336 आदिवासी कारीगरों और कलाकारों की प्रतिभा को उजागर करेगा।
- इस कार्यक्रम में झारखंड के 30 कारीगरों के स्टॉल, लगभग 11 वीडीवीके के स्टॉल और 5 व्यंजन स्टॉल शामिल किये जाएंगे। इस कार्यक्रम में 15 व्यंजन स्टॉलों सहित अन्य राज्यों के 68 कारीगरों के स्टॉलों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा।
- यहाँ कपड़ा, पेंटिंग, आभूषण, धातु, बेंत और बाँस एवं व्यंजन जैसी विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रतिभा का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा।

नोट :

'युवा प्रतिभा' के शीर्ष 20 प्रतिभागियों में राँची के अंकित का चयन

चर्चा में क्यों ?

9 अक्तूबर, 2023 को भारत सरकार की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता 'युवा प्रतिभा' के शीर्ष 20 प्रतिभागियों में राँची के कलाकार अंकित का चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- यह राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता www.mygov.in पोर्टल पर आयोजित की गई थी। इसमें देश के कलाकारों को चित्रकला के माध्यम से पूर्व निर्धारित थीम के बारे में उनके व्याख्यानों को प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया गया था।
- हज़ारों प्रस्तुतियों में से सिर्फ 20 कलाकारों को अंतिम दौर में प्रवेश मिला। इस माह नई दिल्ली में अगला इवेंट आयोजित होगा।
- एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में मैनेजमेंट कंसलटेंट के रूप में काम करने वाले अंकित ने बीआईटी, मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय से अपनी कला यात्रा को जारी रखा है। उन्हें वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग दोनों में उत्कृष्टता हासिल है।
- अंकित चारकोल पोर्ट्रेट कला में भी माहिर हैं। वर्ष 2016 में उन्हें 'झारखंड फाउंडेशन सिटीजन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था।

झारखंड में 'ए-हेल्प 'कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

10 अक्तूबर, 2023 को पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने झारखंड में 'ए-हेल्प' (स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिये मान्यताप्राप्त एजेंट) कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने 'ए-हेल्प' कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करके सशक्त बनाना है। ये एजेंट रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं।
- उन्होंने कहा कि नई
- से किसानों के दरवाज़े तक पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुँच बढ़ेगी और इससे पशु सखियाँ सशक्त होंगी। यह सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने, महिला शक्ति के उल्लेखनीय एकीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार अलका उपाध्याय ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लेते हुए कहा कि पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिये मान्यताप्राप्त एजेंट (ए-हेल्प) नामक समुदाय-आधारित पदाधिकारियों का यह नया बैंड स्थानीय पशु चिकित्सा संस्थानों और पशुधन मालिकों के बीच रिक्त स्थान को भरने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये तैयार किया गया है और यह पशुधन संसाधन व्यक्तियों और प्राथमिक सेवा प्रदाताओं के रूप में सेवा प्रदान करेगा।
- गौरतलब है कि पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने 'ए-हेल्प' (स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिये मान्यता प्राप्त एजेंट) नाम से एक अनूठी पहल शुरू की है और यह बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पहले ही शुरू हो चुकी है।
- पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार के तहत डीएएचडी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से इस उल्लेखनीय पहल की शुरुआत की है।

नोट :

'अमृत' मिशन (AMRUT) के तहत देश के 500 शहरों में झारखंड के पाँच शहर शामिल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT) के तहत देश के 500 शहरों में झारखंड के पाँच शहरों- देवघर, मधुपुर, बासुकिनाथ, गोड्डा और महागामा को शामिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र के इन 5 शहरों के कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये पहले फेज में 50 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिये हैं। इस राशि से इन 5 शहरों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क, आधारभूत संरचना जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं पर काम होगा।

- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में भारत सरकार ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT) शुरू किया था, जिसका उद्देश्य पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएँ प्रदान करना है, ताकि सभी के लिये जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके, विशेषरूप से गरीबों और वंचितों के लिये।
- मिशन का फोकस बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर है, जिसका नागरिकों को बेहतर सेवाओं के प्रावधान से सीधा संबंध है
- 'अमृत' मिशन के उद्देश्य हैं-
  - सुनिश्चित करना है कि हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और एक सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल तक पहुँच हो।
  - हरियाली और अच्छी तरह से बनाए हुए खुले स्थान विकसित करके शहरों की सुविधा मूल्य में वृद्धि करें।
  - सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करके या गैर-मोटर चालित परिवहन के लिये सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना।
- प्रमुख परियोजना घटक प्राथमिकता के क्रम में जल आपूर्ति प्रणाली, सीवरेज, सेप्टेज, तूफान जल निकासी, शहरी परिवहन, हरित स्थान और पार्क, सुधार प्रबंधन और समर्थन, क्षमता निर्माण आदि हैं।
- जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं के सार्वभौमिक कवरेज का मिशन में पहला प्रभार है। बच्चों और बुजुर्गों के अनुकूल सुविधाओं वाले पार्कों के विकास के लिये परियोजना लागत का अधिकतम 2.5% आवंटन है।
- मिशन में 500 शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें अधिसूचित नगर पालिकाओं के साथ एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर और कस्बे शामिल हैं।
- अमृत के लिये कुल परिव्यय रुपए वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 तक पाँच वर्षों के लिये 50,000 करोड़ रुपए थे।
- यह मिशन केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है। परियोजना निधि को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच एक समान सूत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की शहरी आबादी और सांविधिक कस्बों की संख्या को 50:50 वेटेज दिया जा रहा है।

झारखंड में होगा मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

12 अक्तूबर, 2023 को राँची के उपायक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी बीडीओ को खेल कैलेंडर 2023-24 के अनुसार निर्धारित तिथि के अनुरूप 'मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता' कराने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि झारखंड में 'मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल (पुरुष/महिला) प्रतियोगिता 2023-24' का आयोजन कुल पाँच स्तरों- पंचायत, प्रखंड, ज़िला, ज़ोनल एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा।
- प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर राँची के उपायक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा राँची ज़िले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को खेल कैलेंडर 2023-24 के अनुसार निर्धारित तिथि के अनुरूप पंचायतस्तरीय एवं प्रखंडस्तरीय प्रतियोगिता, 2023-24 का आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
- झारखंड के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग अंतर्गत खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल (पुरुष/महिला) प्रतियोगिता के तहत पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने झारखंड के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को किया पुरस्कृत

चर्चा में क्यों ?

12 अक्तूबर, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राँची के खेलगाँव स्थित हरिवंश राय टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित सम्मान राशि वितरण समारोह में खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समारोह में कहा कि पंचायत स्तर पर खेल संस्कृति को और मज़बूत करने के लिये सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब शुरू किया जा रहा है। प्रत्येक क्लब को प्रतिवर्ष 25,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे क्षेत्र, जो नक्सल प्रभावित हैं, वहाँ भी युवाओं को खेल से जोड़कर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से सहाय योजना की शुरुआत की गई है। पिछले वर्ष लगभग 75 हज़ार खिलाड़ियों ने सहाय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस वर्ष इसका दायरा 5 ज़िलों से बढ़ाकर 7 ज़िलों में किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार हॉकी इंडिया एवं राज्य सरकार द्वारा झारखंड वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2023 का आयोजन 27 अक्तूबर से 05 नवंबर, 2023 के बीच किया जा रहा है। इसमें एशिया के 06 देशों की टीमें भाग लेंगी। यह पहला मौका है, जब इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड में किया जा रहा है।
- सीएम ने कहा कि खेल विभाग ने जोहार खिलाड़ी पोर्टल की शुरुआत भी की है। यह पोर्टल देश का पहला ऐसा पोर्टल है, जहाँ खेल और खिलाड़ियों का डाटा एकत्र कर उन्हें हरसंभव मदद की जाएगी। इस पोर्टल में खिलाड़ी और प्रशिक्षकों का पूर्ण विवरण होगा।
- पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि राज्य में नई खेल नीति बनने के बाद पहली बार खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के बीच सम्मान राशि का वितरण किया गया है। 222 खिलाड़ी तथा 48 से अधिक प्रशिक्षकों के बीच लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कारस्वरूप उन्हें प्रदान की गई है।

नोट :

इंस्पायर अवॉर्ड मानक के अंतर्गत आइडिया देने के मामले में झारखंड देशभर में छठे स्थान पर

चर्चा में क्यों?

15 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रतिष्ठित इंस्पायर अवॉर्ड मानक (मिलियन माइंड्स ऑगमेटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज) के अंतर्गत आइडिया देने के मामले में झारखंड देशभर में छठे स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिये इसकी शुरुआत की गई है। झारखंड की ओर से इस वर्ष 40833 छात्रों ने अपने आइडिया का रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-23 में रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य 45 हज़ार रखा था।
- झारखंड से रजिस्ट्रेशन करने के मामले में पलामू (3575), गिरिडीह (3180) और बोकारो (3140) शीर्ष तीन ज़िलों में शामिल हैं। राजधानी राँची से 2382 आइडिया पंजीकृत हुए हैं। राँची पाँचवें स्थान पर है, वहीं लातेहार (723), रामगढ़ (793) और पाकुड़ (849) का प्रदर्शन कमज़ोर रहा।
- झारखंड, बिहार से इस मामले में आगे है, जबकि ओडिशा से यह पीछे है। बिहार 36399 रजिस्ट्रेशन के साथ नौवें स्थान पर रहा। ओडिशा से 59909 छात्रों ने अपने आइडिया का रजिस्ट्रेशन इंस्पायर अवॉर्ड के लिये कराया है।
- सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन राजस्थान (158128), कर्नाटक (112744) और छत्तीसगढ़ (77719) के विद्यार्थियों ने किया है।
- भारत सरकार की ओर से विद्यार्थियों द्वारा दिये गए आइडिया की स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के बाद चयनित आइडिया को मॉडल का रूप देने के लिये विद्यार्थियों को 10-10 हज़ार रुपए दिये जाएंगे। साथ ही इसे और बेहतर बनाने के लिये विद्यार्थी शिक्षकों और अपने राज्यों के नोडल पदाधिकारियों से मदद ले सकेंगे।

राँची के सात वर्षीय छात्र विवान को मिला स्टार आर्टिस्ट अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

16 अक्तूबर, 2023 को राँची के सात वर्षीय छात्र विवान शौर्या ने विश्व की प्रतिष्ठित चित्रकला प्रतियोगिता 'पिकासो आर्ट कॉन्टेस्ट' के क्रिएटिव ब्रिलियंस-2023 में स्टार आर्टिस्ट अवॉर्ड प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- 6 से 10 वर्ष वाले ग्रुप में सात वर्षीय विवान को 100 में से 92 अंक प्राप्त करने पर स्टार आर्टिस्ट सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट प्रदान किया गया। पिछले वर्ष भी विवान ने प्रतियोगिता में यह खिताब जीता था।

नोट :

- इस वर्ष प्रतियोगिता में 38 देशों से 1100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें इटली, हॉन्गकॉन्ग, कनाडा, तुर्की, ऑस्ट्रिया, वियतनाम, रोमानिया, बुल्गारिया, साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं अन्य देश शामिल हैं।
- यह प्रतियोगिता 2014 से प्रत्येक वर्ष आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के सारे मापदंडों पर नवाचार, रचनात्मकता, आकर्षण, पूर्णता, कलाकार की आयु, प्रस्तुति और कलात्मक क्षमता के आधार पर चुनाव किया जाता है।
- विदित हो कि विवान जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली का दूसरी कक्षा का छात्र है। विवान के गुरु और पिता धनंजय कुमार भी प्रख्यात चित्रकार हैं और कालाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स के संस्थापक हैं।
- उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कर विवान ने पेंटिंग्स बनाना शुरु किया और लगभग 150 से अधिक पेंटिंग्स बनाई। इस दौरान विवान ने 21 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय राज्य और ज़िला स्तर के पुरस्कार भी जीते।

स्कूली बच्चों के लिये ऑनलाइन एजुकेशन ऐप 'जे गुरुजी ऐप'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राँची में आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन एजुकेशन के लिये 'जी गुरुजी मोबाइल एप'की लॉन्चिंग की।

प्रमुख बिंदु

- झारखंड के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिये ऑनलाइन शिक्षा मोबाइल ऐप तैयार कराया है। इस ऐप में लॉगिन के लिये विद्यार्थियों को 'स्टूडेंट आइडी' मिलेगी। लॉगिन के बाद छात्र ऑनलाइन क्लास भी कर सकेंगे।
- ऐप पर कक्षा एक से 12वीं तक की सभी किताबें भी उपलब्ध रहेंगी। ऐप में प्रत्येक चैप्टर के अनुरूप सवाल भी दिये गए हैं, जिन्हें विद्यार्थी ऑनलाइन हल कर सकते हैं।
- इस ऐप को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि छात्रों को एक क्लिक पर किताब से लेकर टेस्ट सीरीज़ और सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
- इस ऐप में सवालों के जवाब देने के दौरान किसी प्रश्न का उत्तर गलत होने पर उसके सही उत्तर की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही छात्रों को ये भी बताया जाएगा कि सही उत्तर के लिये वे किताब के किस चैप्टर को देखें।
- वहीं इसमें तकरीबन 2700 ऑनलाइन वीडियो भी अपलोड हैं। ऐप पर विद्यार्थी की पढ़ाई के अनुरूप उन्हें राज्य स्तर पर रैंक भी दी जाएगी।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बने ओडिशा के नए राज्यपाल

चर्चा में क्यों?

18 अक्तूबर, 2023 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- रघुवर दास की नियुक्ति राज्यपाल पद का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। रघुवर दास नियुक्ति के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की ज़िम्मेदारी संभाल रहे थे।
- रघुवर दास झारखंड के पहले गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं।
- वर्ष 2000 में झारखंड के गठन के बाद रघुवर दास अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले सीएम थे।

15 नवंबर को राँची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का होगा भूमि पूजन

चर्चा में क्यों?

19 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राँची स्मार्ट सिटी परिसर में 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अपोलो मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का भूमि पूजन करने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- राँची स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में अपोलो अस्पताल के निर्माण के लिये राँची नगर निगम और अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड, चेन्नई के बीच सब लीज डीड पर हस्ताक्षर हुआ है।
- अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ यह समझौता विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

नोट :

- अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि जल्द ही 250 बेड के अस्पताल निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पहले चरण में यहाँ ओपीडी की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्थानीय लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी।
- अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज के द्वारा राँची स्मार्ट सिटी परिसर में लगभग 2.75 एकड़ ज़मीन में 250 बेड वाले मल्टी सुपर स्पेलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। यहाँ विशेषरूप से कॉर्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी सेवा प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा इमरजेंसी सेवा, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, डाइटरी सर्विसेस की भी व्यवस्था यहाँ होगी। अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध रहेगी। हॉस्पिटल के अंदर पार्किंग, फार्मेसी, एटीएम, कैंटीन इत्यादि की व्यवस्था भी रहेगी।
- राँची स्मार्ट सिटी परिसर में कई इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेज, पाँच सितारा समेत कई होटल, मॉल, ऑफिस तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ लगभग 16 हज़ार आवासीय इकाई होंगी और अनुमानित है कि लगभग डेढ़ लाख की जनसंख्या इस विकसित क्षेत्र में निवास करेगी, जो इस परियोजना से सीधे रूप से लाभान्वित होगी।

राँची को एक और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मिली मेज़बानी

चर्चा में क्यों?

21 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड की राजधानी राँची में एक और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप होगी, जो 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिये क्वालीफाइंग चैंपियनशिप होगी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) ने महिला ओलंपिक क्वालीफायर की मेज़बानी भारत (राँची) को सौंपी है। पहले यह क्वालीफायर चीन के चांगझोउ में होना था, लेकिन अब 13 से 19 जनवरी तक इसका आयोजन राँची (मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम) में होगा।
- इस क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में भारत के अलावा सात देश हिस्सा लेंगे, जिनमें से शीर्ष तीन अगले साल के ओलंपिक में अपनी जगह पक्की करेंगे।
- एफआइएच के अन्य ओलंपिक क्वालीफायर मस्कट, ओमान (पुरुष, 15-21 जनवरी, 2024) और वेलेंसिया, स्पेन (महिला और पुरुष, 13-21 जनवरी, 2024) में खेले जाएँगे।
- विदित है कि हाल ही में चीन के हांगझोउ में हुए एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम तीसरे स्थान पर रही थी और पेरिस ओलंपिक के लिये क्वालीफाई करने से चूक गई थी।
- भारत हांगझोउ एशियाई खेलों की महिला हॉकी सेमीफाइनल में मेज़बान चीन से 0-4 से हार गया था। टीम को इसके बाद जापान को 2-1 से हराकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
- उल्लेखनीय है कि ओलंपिक क्वालीफायर से पहले भारतीय टीम 27 अक्तूबर से पाँच नवंबर तक राँची में ही महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी। टूर्नामेंट में घरेलू टीम का सामना जापान, चीन, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड से होगा।

'अबुआ आवास योजना' के लिये अलग से गठित होगी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट

चर्चा में क्यों?

23 अक्तूबर, 2023 को राज्य सरकार ने 'अबुआ आवास योजना' के तहत लोगों को आवास मुहैया कराने से लेकर कार्य संपादन तक की ज़िम्मेदारी के निर्वाहन के लिये अलग से प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) गठित करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- पीएमयू के पास लाभुकों के चयन से लेकर अनुबंधकर्मियों की नियुक्ति और सामाजिक अंकेक्षण तक की ज़िम्मेदारी होगी।

- वर्ष 2026 तक आठ लाख आवासों का निर्माण किया जाना है। नए तीन कमरों के आवास का निर्माण दो लाख रुपए की लागत से किया जाएगा और यह राशि राज्य सरकार के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध होगी।

- इसके लिये 331 वर्ग मीटर में निर्माण के लिये शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। लक्ष्य के अनुरूप इस योजना के अंतर्गत राशि का प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के वार्षिक बजट में किया जाएगा।
- राज्य स्तर पर कार्यक्रम निधि का 2 प्रतिशत राज्य स्तर पर योजना के प्रशासनिक संचालन के लिये उपलब्ध होगा तथा इस राशि का आवंटन ज़िलों को मांग एवं उपयोगिता के आधार पर किया जाएगा।
- आईटी (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) और संचार प्रणालियों के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी, कार्यालय-व्यय, आकस्मिक व्यय/ डाटा एंट्री आदि कार्य भी पीएमयू के माध्यम से किये जाएंगे।

- इसके अतिरिक्त पीएमयू की स्थापना और संचालन का व्यय, जिसमें बीमा ईपीएफ, चिकित्सा बीमा इत्यादि अनुमान्य लाभसहित अनुबंध पर कर्मियों की नियुक्ति करना भी शामिल है। राजमिस्त्री के प्रशिक्षण और प्रमाणन की लागत एवं अन्य आवश्यक प्रशिक्षण का व्यय भी पीएमयू के माध्यम से होगा।
- इसके अलावा इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन गतिविधियों के संचालन के साथ-साथ पुरस्कार के वितरण, समीक्षा बैठकों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन भी पीएमयू के पास ही होगा।
- ग्राम पंचायत से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में प्राथमिक लाभुकों की सूची का दीवार लेखन, प्रशिक्षित राजमिस्त्री की सूची का दीवार लेखन आदि का उत्तरदायित्व पीएमयू का है।
- इसके साथ ही क्लस्टर रिसोर्स पर्सन को मानदेय और गैर-सरकारी संगठनों को सेवा शुल्क का भुगतान भी पीएमयू के माध्यम से किया जाएगा।

प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडेय को मिला 'लाडली मीडिया अवॉर्ड'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था 'पॉपुलेशन फर्स्ट' द्वारा प्रभात खबर के रांची यूनिट के वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडेय को 'लाडली मीडिया अवॉर्ड्स 2023' से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि 'पॉपुलेशन फर्स्ट'संस्था की ओर से लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिये लाडली मीडिया अवॉर्ड दिया जाता है। संस्था द्वारा लाडली मीडिया अवॉर्ड की घोषणा इस साल 21 अक्तूबर को की गई थी।
- इस अवॉर्ड के लिये देश भर से 13 भाषाओं के करीब 850 से ज्यादा पत्रकारों ने प्रविष्टियां भेजी थी, जिनमें जूरी मेंबर्स ने 87 का चयन किया और उन्हें सम्मानित किया। इनके अलावा 31 पत्रकारों को जूरी प्रशंसा पत्र दिया गया।

- पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था की ओर से आयोजित 13वें लाडली मीडिया एंड एडवरटाइजिंग अवॉर्ड फॉर जेंडर सेंसिटिविटी (रीजनल) 2023 में प्रभात खबर को अवार्ड मिला है। पिछले वर्ष भी प्रभात खबर के एक अन्य पत्रकार गुरुस्वरूप मिश्रा को भी इस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।
- प्रभात खबर रांची यूनिट के मुख्य संवाददाता राजीव पांडेय द्वारा प्रकाशित घरेलू कामगारों पर एक स्टोरी 'घरेलू कामगारों की स्थिति खराब, न छुट्‌टी और न उचित मेहताना' के लिये उन्हें अवॉर्ड मिला।
- जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति प्रो. डॉ. देव स्वरूप, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के पॉलिसी व साझेदारी प्रमुख जयदीप बिस्वास, यूएनएफपीए की प्रोग्राम मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट अनुजा गुलाटी और लोक संवाद संस्थान के सचिव कल्याण सिंह कोठारी ने राजीव पांडेय को सम्मानित किया।
- गौरतलब है कि राजीव पांडेय को इससे पहले भी चेन्नई की संस्थान रीच द्वारा तीन फेलोशिप अवॉर्ड दिया गया है। वर्ष 2014 में टीबी की बीमारी में झारखंड की स्थिति पर, वर्ष 2019 में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और वर्ष 2023 में डायबिटीज पर फेलोशिप प्राप्त हुआ है।

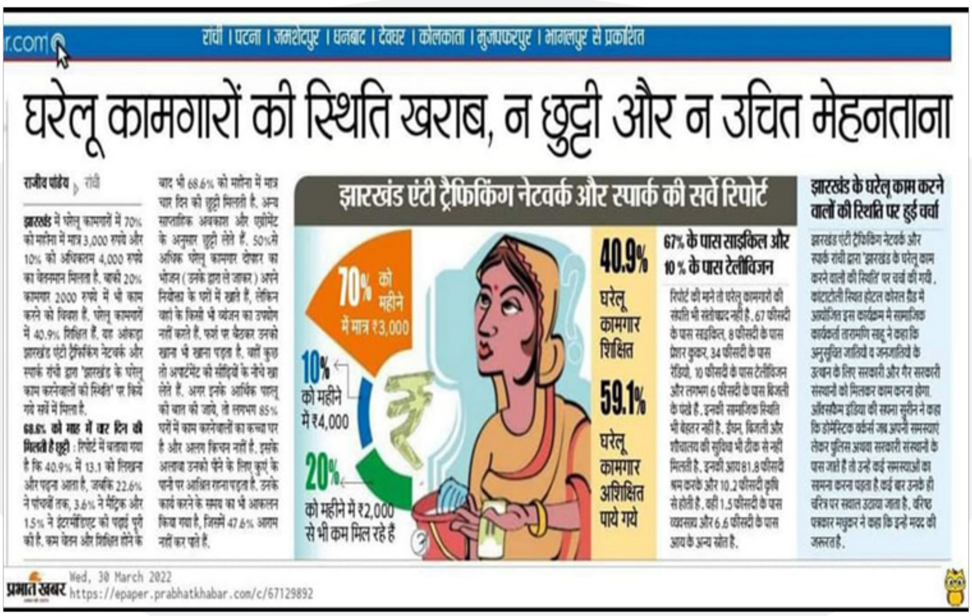

रांची | पटना | जमशेदपुर | धनबाद | देवघर | कोलकाता | मुजफ्फरपुर | भागलपुर से प्रकाशित

घरेलू कामगारों की स्थिति खराब, न छुट्टी और न उचित मेहनताना

राजीव पांडेय, रांची

झारखंड में घरेलू कामगारों में 70% को महीना में मात्र 3,000 रुपये और 10% को अधिकतम 4,000 रुपये का वेतनमान मिलता है. बाकी 20% कामगार 2000 रुपये में भी काम करने को विवश हैं. घरेलू कामगारों में 40.9% शिक्षित हैं. यह आंकड़ा झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क और स्पार्क रांची द्वारा 'झारखंड के घरेलू काम करनेवालों की स्थिति' पर किये गये सर्वे में मिला है.

68.6% को माह में चार दिन की मिलती है छुट्टी : रिपोर्ट में बताया गया है कि 40.9% में 13.1 को लिखना और पढ़ना आता है, जबकि 22.6% ने पांचवीं तक, 3.6% ने मैट्रिक और 1.5% ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की है. कम वेतन और शिक्षित होने के बाद भी 68.6% को महीना में मात्र चार दिन की छुट्टी मिलती है. अन्य साप्ताहिक अवकाश और एग्रीमेंट के अनुसार छुट्टी लेते हैं. 50% से अधिक घरेलू कामगार दोपहर का भोजन (उनके द्वारा ले जाकर) अपने नियोक्ता के घरों में खाते हैं, लेकिन वहां के किसी भी व्यंजन का उपयोग नहीं करते हैं. फर्श पर बैठकर उनको खाना भी खाना पड़ता है. वहीं कुछ तो अपार्टमेंट की सीढ़ियों के नीचे खा लेते हैं. अगर इनके आर्थिक पहलू की बात की जाये, तो लगभग 85% घरों में काम करनेवालों का कच्चा घर है और अलग किचन नहीं है. इसके अलावा उनको पीने के लिए कुएं के पानी पर आश्रित रहना पड़ता है. उनके कार्य करने के समय का भी आकलन किया गया है, जिसमें 47.6% आराम नहीं कर पाते हैं.

झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क और स्पार्क की सर्वे रिपोर्ट

67% के पास साइकिल और 10 % के पास टेलीविजन

रिपोर्ट की मानें तो घरेलू कामगारों की संपत्ति भी संतोषजनक नहीं है. 67 फीसदी के पास साइकिल, 8 फीसदी के पास प्रेशर कुकर, 34 फीसदी के पास रेडियो, 10 फीसदी के पास टेलीविजन और लगभग 6 फीसदी के पास बिजली के पंखे हैं. इनकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर नहीं है. ईंधन, बिजली और शौचालय की सुविधा भी ठीक से नहीं मिलती है. इनकी आय 81.8 फीसदी श्रम करके और 10.2 फीसदी कृषि से होती है. वहीं 1.5 फीसदी के पास व्यवसाय और 6.6 फीसदी के पास आय के अन्य स्रोत हैं.

झारखंड के घरेलू काम करने वालों की स्थिति पर हुई चर्चा

झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क और स्पार्क रांची द्वारा 'झारखंड के घरेलू काम करने वालों की स्थिति' पर चर्चा की गयी. कांटाटोली स्थित होटल कोरल ग्रैंड में आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता तारामणि साहू ने कहा कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के उत्थान के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को मिलकर काम करना होगा. ऑक्सफैम इंडिया की सक्सेना सुरीन ने कहा कि डोमेस्टिक वर्कर्स जब अपनी समस्याएं लेकर पुलिस अथवा सरकारी संस्थानों के पास जाते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है कई बार उनके ही चरित्र पर सवाल उठाया जाता है. वरिष्ठ पत्रकार मधुकर ने कहा कि इन्हें मदद की जरूरत है.

प्रभात खबर Wed, 30 March 2022 https://epaper.prabhatkhabar.com/c/67129892

नोट :

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) का डिजि लॉकर नवंबर से ऑनलाइन

चर्चा में क्यों?

29 अक्तूबर, 2023 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के सचिव एसडी तिग्गा ने बताया कि डिजि-लॉकर तैयार कर लिया गया है। इसे नवंबर से छात्र-छात्राओं के लिये ऑनलाइन कर दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सचिव एसडी तिग्गा ने बताया कि डिजि-लॉकर में 2023 तक की सभी परीक्षाओं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिये गए हैं। इसमें एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड जाने वाले विद्यार्थियों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया गया है। छात्र-छात्रा मूल प्रमाणपत्र व अंक पत्र खो जाने पर डुप्लिकेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑनलाइन निकाल सकेंगे।
- वहीं जैक ने वेरिफिकेशन सिस्टम भी डेवलप किया है। जैक के स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी। इसे पब्लिक डोमेन पर रखा जाएगा।
- इसमें कोई भी छात्र-छात्रा अपना नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि व पास करने का वर्ष डालकर जानकारी ले सकेगा। इस व्यवस्था से सबसे ज़्यादा मार्क्सशीट व सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी मिलेगा।
- दूसरी जगहों में नामांकन से लेकर नियुक्ति में संस्थान सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिये सर्टिफिकेट की प्रति भेजने और उसकी जाँच रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं करना होगा।
- सर्टिफिकेट में सुधार एडमिट कार्ड, मार्क्सशीट व सर्टिफिकेट में गलती को जैक ऑनलाइन सुधार करेगा। सुधार होने के बाद छात्र-छात्रा इसे ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे।
- निर्धारित शुल्क और सर्टिफिकेट के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक इसे ऑनलाइन फॉरवर्ड (अग्रसारित) करेंगे। एक निश्चित समय-सीमा में जैक इसमें सुधार कर भेज देगा।

मुख्यमंत्री ने झारखंड के सबसे लंबे पुल व 21 अन्य योजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

30 अक्तूबर, को 2023 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के कुमड़ाबाद में मयूराक्षी नदी पर बनाए गए राज्य के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया। साथ ही 543 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार व बनने वाली 21 अन्य योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- 198 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल की लंबाई 2.34 किलोमीटर है। पुल का नामकरण दिशोम गुरु शिबू सोरेन सेतु किया गया है।
- उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल के बन जाने से दुमका मसलिया और रानेश्वर प्रखंड के दर्जनों गाँवों के लोगों के लिये आवागमन सुगम हो जाएगा।
- पुल के बनने से न सिर्फ पश्चिम बंगाल, राँची, जामताड़ा व नाला की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि इससे आर्थिक व पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा।

नोट :